क्र॰ सं॰	जिले का नाम	एककों की संख्या	नियोजित व्यक्तियों की संख्या
51.	मिर्जापुर	4685	19113
52.	सोनभद्र	2475	13445
53.	भदोही	449	2051
54.	बस्ती	3666	14189
55.	कबीर नगर	-	-
56.	सिद्धार्थ नगर	1973	7750
57.	गोरखपुर	3657	12906
58.	देवरिया	4314	17686
59.	महाराजगंज	2257	7956
60.	कुशी नगर	350	661
61.	आजमगढ़	3170	14554
62.	बलिया	5437	18845
63.	माऊ	2335	6733
64.	फैजाबाद	4991	19480
65.	बाराबंकी	5283	15619
66.	सुल्तानपुर	5907	21286
67.	अम्बेडकर नगर	252	605
68.	गोंडा	4335	15887
69.	बहराईच	3663	14401
70.	श्रावस्ती नगर	94	206
71.	बलराम पुर	73	219
72.	देहरादून	2569	8906
73.	पौड़ी गढ़वाल	2643	8280
74.	टिहरी गढ़वाल	2550	7946
75.	चमोली	2548	6025
76.	रूद्र प्रयाग	48	87
77.	उत्तरकाशी	2045	5449
78.	नैनीताल	3858	12513
79.	अल्मोड़ा	4441	14157
80.	पिथौड़ागढ़	2160	4859
81.	बगेश्वर	-	-
82.	चम्पावत	-	-
83.	उधमसिंह नगर	783	1187
84.	नोएडा	3980	39505
85.	ग्रेटर नोएडा	30	573
	योग	342812	1420602

Working capital in Jessop and Company Ltd.

490. SHRI NILOTPAL BASU:
SHRIMATI CHANDRA KALA PANDEY:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the newsitem "Ailing Jessop defers account by three months" that appeared in the Telegraph dated 13th May,.1998;

(b) whether the Company has suffered because of shortage of working capital;

(c) if so, the steps taken to augment the working capital; and

(d) the statutory dues payable to the workers on roll as well as to the retired workers as on date?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) A news item, as mentioned, was published by the Telegraph.

(b) and (c) The Company has suffered due to many factors including working capital shortage. Government has provided counter guarantee of Rs. 10 crore to banks for extending working capital facility Rs. 16.84 crores was also provided by the Government as non-plan assistance in the year 1997-98 besides Rs. 6 crores for Voluntary Retirement Scheme (VRS).

(d) The statutory dues payable to employees on roll as well as to the retired emplyees as on 31.3.98 are as under:—

(i) Salary & Wages	Rs. 6.75 crores
(ii) Gratuity	Rs. 11.46 crores
(iii) Provident Fund	Rs. 37.10 crores.

लघु उद्योगों में औद्योगिक रुग्णता

491. **श्री बरजिन्दर सिंह:**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में गत वर्षों में लघु उद्योग क्षेत्र में रुग्णतर की समस्या बढ़ी है;

(ख) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों अर्थात् 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 में रुग्ण लघु उद्योगों की वर्ष-वार संख्या क्या थी; और

(ग) इन रुग्ण इकाइयों में वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुल कितनी राशि का निवेश किया गया था?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) से (ग) जी नहीं। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मार्च, 1997 तक एकत्र किए गये नवीनतम आंकड़ों के अनुसार रुग्ण लघु उद्योगों की संख्या पिछले तीन वर्षों के दौरान कम हो गयी है। रुग्ण एककों तथा उनके प्रति बकाया राशि के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

अन्त तक	कुल रुग्ण उद्योग एककों की संख्या	बकाया राशि (करोड़ रुपयों में)
मार्च, 1995	2,68,815	3647.16
मार्च, 1996	2,62,376	3721.94
मार्च, 1997	2,35,032	3609.20

वर्ष 1997-98 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आंकड़े अभी एकत्र किए जाने हैं।

लघु उद्योगों के लिए कार्यशील पूंजी

492. श्री बरिन्दर सिंह:
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा गठित पी०आर० नायक समिति ने लघु उद्योग क्षेत्र में चलाये जा रहे लघु उद्योगों को कार्यशील पूंजी के रूप में 20 प्रतिशत ऋण देने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि वर्ष 1996-97 के दौरान इस शीर्ष के अन्तर्गत केवल 6 प्रतिशत से 7 प्रतिशत की राशि प्रदान की गई थी;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार का आकलन क्या है; और

(घ) 1998-99 के चालू वर्ष के दौरान लघु उद्योगों को कार्यशील पूंजी देने से संबंधित दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) जी हां। यह सच है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित नायक समिति ने सिफारिश की कि लघु इकाइयों को प्राक्षिप्त वार्षिक निष्पादन के 20 प्रतिशत के आधार पर कार्यशील पूंजी वित्त उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

(ख) और (ग) यह अनुमान लगाया गया है कि 1996-97 में कार्यशील पूंजी वित्त प्राक्षिप्त वार्षिक निष्पादन का 7.8 प्रतिशत था। लघु उद्योग क्षेत्र के लिए ऋण की मात्रा में वृद्धि करना सरकार का प्रयास रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार लघु उद्योगों लिए बकाया ऋण की रकम मार्च, 1996 के अन्त में 29,485 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च, 1997 के अन्त तक 31,542 करोड़ रुपये हो गयी। सार्वजनिक क्षेत्र ने बैंकों द्वारा निवल बैंक ऋण की प्रतिशतता के रूप में लघु क्षेत्र का हिस्सा मार्च, 1996 के अंत में 16.0 प्रतिशत से बढ़कर मार्च, 1997 के अन्त तक 16.6 प्रतिशत हो गई है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को निम्नलिखित सलाह दी गई है:-

(1) ग्रामीण उद्योग तथा अति लघु उद्योगों सहित जिन लघु उद्योग इकाइयों की बैंकिंग पद्धति से 2 करोड़ रु० तक की कार्यशील पूंजी आधारित कुल वित्त की अनावश्यकता है, उन्हें प्राक्षिप्त वार्षिक उत्पादन के 20 प्रतिशत के आधार पर संगणित कार्यशील पूंजी सीमा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(2) सुनिश्चित करने के लिए कि लघु उद्योग क्षेत्र को निधियों के उनके कुल आबंटन में से 40 प्रतिशत उन इकाइयों को उपलब्ध कराये जाते हैं जिनके संयंत्र तथा मशीनरी में 5 लाख रुपये तक का निवेश है, 20 प्रतिशत उन इकाइयों को उपलब्ध कराया जाता है जिनके संयंत्र मशीनरी में निवेश 5 लाख तथा 25 लाख के बीच है और शेष 40 प्रतिशत अन्य लघु उद्योग इकाइयों को उपलब्ध कराया जाते हैं।

(3) और अधिक विशेषज्ञ लघु उद्योग बैंक शाखायें चलाना।

(4) ऋण आवेदनों को निपटाने में विलम्ब से बचने के लिए किस दृष्टि से विशेषज्ञ लघु उद्योग बैंक शाखाओं के प्रबन्धकों को पर्याप्त शक्तियां प्रदान करना।

(5) ऋण आवेदनों की निर्धारित समय सीमा, 8 से 9 सप्ताह से अनअधिक अवधि के भीतर निपटाया जाना चाहिए।

दरभंगा, बिहार में प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण

493. चौधरी हरमोहन सिंह यादव: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दरभंगा, बिहार में प्रधान मंत्री रोज़गार योजना के अन्तर्गत 1995 से अब तक कितना ऋण दिया गया है;